SHRI V. KISHORE CHANDRA S. DEO: May I know whether it is not against the public interest to allow the private sector to come into this vital production sector which has so far been done by the public undertakings. Just now, the Minister himself said that it is against the public interest to disclose even the figures of the last five years. But when it is given to the private trade, they will automatically know the number of trucks that have been manufactured. What is the policy of the Government? Will you continue to encourage private sector in the production of vital items?

PROF. SHER SINGH: It is a much wide question. We have stated several times on the floor of this House that the critical items will be produced in the public sector only. We can take from the civil sector where the capacity exists non-critical items. Sub-assembly and components, but components of critical nature will be manufactured in the public sector.

SHRI VAYALAR RAVI: Why do the Government allow private sector to come in?

MR. SPEAKER: He has mentioned that the present capacity is not sufficient and in the Sixth Plan, they are taking steps.

डा० रामजी सिंह: अध्यक्ष महोदय, क्या प्रतिरक्षा मंत्री बतायेंगे कि देश की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय हित में वे ट्रकों के निर्माण कार्य और उसके कारखानो का राष्ट्रीयकरण करने के पक्ष में हैं? यदि हां, तो कब तक राष्ट्रीयकरण करेंगे और यदि नहीं, तो क्या ऐसा न करने से राष्ट्र का नुकसान नहीं हो सकता है?

प्रो० शेर सिंह: प्रतिरक्षा के सम्बन्ध में, मैंने निवेदन किया कि हम कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं, छठी योजना में जितने ट्रक्स की जरूरत होगी वह हम उम्मीद करते है कि हम पैदा कर सकेंगे। रही बात नेशनलाईजेशन की, दूसरे ट्रक्स के बारे में, तो वह मैं समझता हूं जरूरी नहीं है।

Heavy Water for Atomic Reactor Plants

*785. SHRI DURGA CHAND: Will the Minister of ATOMIC ENERGY be pleased to state:

(a) what is the total requirement of Heavy Water for our Atomic Reactor Plants, plant-wise;

(b) what is the amount under foreign exchange incurred on the import of Heavy Water during the last 3 years, year-wise; and

(c) what steps are being taken to produce this item indigenously?

THE PRIME MINISTER (SHRI MORARJI DESAI): (a) The requirement of heavy water, plant-wise is as indicated below:

Rajasthan Atomic Power Project Unit-I	20 Tonnes/year towards make up.
Rajasthan Atomic Power Project Unit-II	250 Tonnes towards initial charge and 15 Tonnes/year towards make up on reaching stabilised operation.
Madras Atomic Power Project Unit-I	Initial charge of 250 Tonnes at the time of commissioning and estimated make up requirement of 12 Tonnes/year on reaching stabilised operation.
Madras Atomic Power Project Unit-II	Do.

Narora Atomic Power Project (Unit I & II) . 260 Tonnes for each unit for initial inventor at the time of commissioning and 10 tonnes unit per year towards make up on reach ing stabilised operation.

(b) The total expenditure on the import of heavy water during the last three years amounts to Rs. 11,20,32,397 as per details below:—

1975-76	1976-77	1977-78
Nil	8,00,69,571	3,19,62,826

(c) The heavy water plant in operation at Nangal is producing about 14 tonnes of heavy water per year. To meet the requirements of heavy water for the atomic power stations, construction of four heavy water plants have been undertaken, one each at Kota, Baroda, Tuticorin and Talcher with a total production capacity of 300 tonnes per annum.

श्री दुर्गा चन्द : हमारे यहां जो चार एटामिक पावर प्लाट्स हैं, इनकी हैवी-वाटर और यूरेनियम की जरूरत को हम इम्पोर्ट कर के पूरा करते हैं । इसलिये मैं प्रधान मंत्री जी से जानना चाहता हू—इस वक्त जो हमारे चार प्लांट्स लगे हुए हैं, उनकी हैवी वाटर की जरूरत 1000 टन की है, जब कि हम जो चार हैवी-वाटर बनाने के प्लाट्स लगाने जा रहे हैं, उन से केवल 300 टन हैवी वाटर पैदा होगा, ऐसी स्थिति मे जो 700 टन की कमी रहेगी, उसके लिये हम को इम्पोर्ट करना पडेगा । क्या सरकार इस बारे मे विचार कर रही है कि हैवी वाटर के कुछ और प्लांट्स लगाये जायें ताकि हम अपनी जरूरत के मुताबिक यहीं पर हैवी वाटर पैदा कर सके और हम को इम्पोर्ट न करना पडे ।

श्री मोरारजी देसाई : हम को 1000 टन हैवी-वाटर एक साथ नही चाहिये । इस वक्त तारापुर का प्लाट चल रहा है, राजस्थान का एक हिस्सा चल रहा है, दूसरा अभी कमीशन नही हुआ है, वह थोडी देर से कमीशन होगा, मद्रास का प्लाट दिसम्बर, 1979 में कमीशन होगा, उसका दूसरा हिस्सा 1981 मे कमीशन होगा, नरोरा का एक हिस्सा दिसम्बर, 1982 में होगा, दूसरा 1983 मे होगा । इसलिये हर साल 250–300 टन से ज्यादा नही चाहिये और इतना हम प्रोडयूस कर सकते हैं । इसके आलावा कुछ और हैवी-वाटर प्लांट लगाने के बारे मे भी हम सोच रहे हैं ।

श्री दुर्गा चन्द : मेरे प्रश्न के (बी) भाग के जवाब मे कहा गया है कि पिछले दो वर्षों मे हम ने जो हैवी-वाटर इम्पोर्ट किया है, उस पर करीब 11 करोड़ रुपये का फारन एक्सचेन्ज लगा है और इस साल के बजट मे इसकी खरीद के लिये करीब 29 करोड़ रुपया रखा गया है । मैं प्रधान मंत्री जी से जानना चाहता हू—इस साल आप कितना हैवी-वाटर इम्पोर्ट कर रहे है—अपने एटोमिक-पावर प्लाट्स के लिये ?

श्री मोरारजी देसाई : इस साल कितना इम्पोर्ट कर रहे है—इस के बारे मे नोटिस देंगे तो जरूर बतलाऊगा ।

SHRI M. S. SANJEEVI RAO: The hon. Prime Minister is very well aware what a mess we are in, in getting enriched uraniam....

MR. SPEAKER: This is about heavy water.

SHRI M. S. SANJEEVI RAO: I am coming to that.

Now, again, we are getting into similar trouble in getting heavy water from other countries. He is promising that we will be self-reliant in atomic energy power stations. But this is a very vital element, that is, heavy water. We are all aware that there is a big blast that has taken

place in Baroda. I want to know categorically from the Prime Minister whether he is going to take effective steps to see that we produce enough heavy water and see that we become self-sufficient in atomic power stations.

SHRI MORARJI DESAI: We are trying to do our best, but doing our best also cannot account for accidents.

श्री कंवर लाल गुप्त : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय प्रधान मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि यह जो हैवी वाटर है, इसको आप किन-किन देशों से इम्पोर्ट करते हैं और जैसा कि अभी प्रधान मंत्री जी ने कहा कि 300 टन हम बना लेंगे तो इस में हम कब तक पूरी तरह से सैल्फ-रिलायन्ट हो जाएंगे और यह 300 टन कब तक हमारे हिन्दुस्तान में बनने लगेगा और ऐसी स्थिति जल्दी ही कब तक आएगी कि हमें बाहर से इस का इम्पोर्ट न करना पड़े ?

श्री मोरारजी देसाई : अभी ज्यादातर रूस से आता है और मेरा विश्वास है कि दो साल में हम पूरा प्रोड्यूस करने लगेंगे ।

SHRI KRISHAN KANT: May I know whether the enquiry which was ordered by you—due to blast of the Baroda Plant—has been completed and what findings have been given by the finding committee?

SHRI MORARJI DESAI: I cannot give final opinions about it. But what has happened so far what has been done so far shows that it was an accident and not the case of sabotage.

विद्युत् पारेषण (ट्रांसमिशन) लाइनों के बारे में मध्य प्रदेश का प्रस्ताव

*786. **श्री सुभाष आहूजा :** क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) मध्य प्रदेश सरकार ने आर० ई० सी० योजनाओं के अन्तर्गत किन-किन विद्युत पारेषण लाइनों को मंजूरी के लिये प्रस्ताव प्रस्तुत किये हैं ; और

(ख) उन पर केन्द्रीय सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

THE MINISTER OF ENERGY (SHRI P. RAMACHANDRAN): (a) No scheme for Power Transmission Line of Madhya Pradesh is pending with the Rural Electrification Corporation Ltd. for sanction at present.

(b) Does not arise.

श्री सुभाष आहूजा । अध्यक्ष महोदय, मैंने अपने प्रश्न में यह पूछा था कि मध्य प्रदेश सरकार ने आर० ई० सी० योजनाओं के अन्तर्गत किन-किन विद्युत पारेषण लाइनों की मंजूरी के लिये प्रस्ताव भेजे हैं । मैंने उन विद्युत पारेषण लाइनों के नाम पूछे हैं ?

SHRI P. RAMACHANDRAN: Sir, the Madhya Pradesh Government has submitted four special transmission schemes involving a loan assistance of Rs. 2.52 crores and the names of the schemes are: Dhar & Ratlam district—Rs. 35 lakhs, Sehore & Dewas—Rs. 60 lakhs—Dhar district—Rs. 61 lakhs and Mahasumand tehsil of Raipur district—Rs. 94 lakhs. The total comes to Rs. 2.52 crores.

श्री सुभाष आहूजा : अभी माननीय मंत्री जी ने बताया है कि मध्य प्रदेश सरकार ने चार स्कीमों के लिए प्रस्ताव भेजे हैं । तो मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि मंत्री जी उन स्कीमों के लिए कब स्वीकृति देने वाले हैं और वे कब तक शुरू हो जाएंगी ? इस के साथ ही यह भी कहना चाहता हूं कि ग्राम विद्युतीकरण की योजनाओं के लिए राज्य सरकारों को ग्राम विद्युतीकरण निगम पैसा देता है लेकिन इस समय जो ग्राम विद्युतीकरण निगम के मापदंड हैं वे बहुत ही कठिन हैं जिन को आदिवासी क्षेत्रों में लागू नहीं किया जा सकता । तो मैं माननीय मंत्री जी से यह निवेदन करूंगा कि मध्य प्रदेश के जो आदिवासी क्षेत्र हैं उनके